



VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS

R
N

16 SEP 2018

NO.
03

RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1072)

Name of Candidate	सुनिल कुमार धनवन्ता		
Medium Eng./Hindi	हिन्दी	Registration Number	109506
Center	KB	Date	16/09/18

INDEX TABLE		
Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

- Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
- There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI** इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
- All questions are compulsory.**
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
- Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

M-1/4, Plot No-A-12/13, 1st Floor, Ansal Building, Dr. Vidya Sagar Homeopathic Clinic, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. Explain why it is important to urgently address the problem of poor land records and infirmity of land titles in India. Also discuss how this problem can be addressed. (150 Words) 10

व्याख्या कीजिए कि भारत में खराब भू-अभिलेखों एवं भूमि अधिकारों के सुदृढ़ नहीं होने की समस्या का तत्काल समाधान करना क्यों महत्वपूर्ण है। साथ ही, चर्चा कीजिए कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है।

भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि की दशा सुधारने के लिए भूमि सुधारों के अंतर्गत भू-अभिलेखों में सुधार तथा भूमि अधिकारों में सुधार का प्रयास किया गया।

परन्तु आज तक भी यह कार्य अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाया है।

आवश्यकता क्यों?

→ भू-अभिलेखों के खराब रिकॉर्ड के कारण भूमि विवादों का जन्म

→ चक्रवर्ती कार्यक्रम के समझ समस्या

→ लगान शकजित करने में समस्या

→ भू-अधिकारों के सुदृढ़ नहीं होने के

कारण कृषकों में आत्मविश्वास की कमी

तथा निम्न उत्पादन की समस्या

→ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे उपाय अपनाने में समस्या ।

→ 'नक्सलवाद' आंदोलन जैसी समस्या का जन्म उत्पादि ।

समस्या का समाधान -

(i) भू-अभिलेखों के इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करने पर बल जैसे ~~कानून~~ कानून का भूमि प्रोजेक्टर

(ii) विस्तृत कृषि भूमि सर्वेक्षण

(iii) कृषि भूमि पर कृषि कर रहे जोतदारों को अधिकारों ~~को~~ देना

(iv) जमींदारी उन्मूलन कानून का सही क्रिया-कथन

इसी के साथ नौकरशाही में भ्रष्टाचार व लापरवाही को कम कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

2. What are the special features of the infrastructure sector that make its financing a challenge? What measures have been taken to facilitate adequate amount of finance to this sector?

(150 Words) 10

अवसंरचना क्षेत्रक के वे विशेष लक्षण क्या हैं जो इसके वित्तीयन को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं? इस क्षेत्रक में वित्त की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन-से उपाय किए गए हैं।

भारत वर्तमान में निम्नस्तरीय व
अपर्याप्त अवसंरचना के कारण विकास में अवरोध
की समस्या से ग्रस्त रहा है।

अवसंरचना क्षेत्र के वित्तीयन में चुनौतियाँ

- अवसंरचना विकास के आधार के विस्तृत होने के कारण विशाल मात्रा में पूंजी की आवश्यकता।
- इन परिभाषनाओं पूंजी पर लाभ की प्राप्ति अनेक वर्षों के पश्चात् प्राप्त होने के कारण निवेशकों में स्वल्प का अभाव
- पर्यावरण संबंधी मंजूरीयों में विलंब के कारण परियोजना के अटकने के फलस्वरूप

निवेशकों की पूंजी का फंसना।

- बैंक इस क्षेत्र को तटस्थ देने में अनिच्छा का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि ये 'NPA' के बड़े स्रोत हैं।

~~समाधान के~~

विभिन्न सुनिश्चित करने के उपाय-

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर ध्यान देना
- पर्यावरण मंजूरीयों की प्रक्रिया को तीव्र बनाने का प्रयास करना
- इस क्षेत्र की 'NPA' की समस्या का तत्काल समाधान करना ताकि बैंक तटस्थ देने के लिए आगे आए

इसी के साथ विदेशी निवेश की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी तीव्र प्रयास करना चाहिए।

3. Despite favourable circumstances, India's electronics manufacturing has been unable to respond to the rising demand. Discuss. What steps can be taken to address this situation? (150 Words) 10

अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण बढ़ती मांग के प्रति अनुक्रिया करने में असमर्थ रहा है। चर्चा कीजिए। इस परिस्थिति को संबोधित करने के लिए कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं?

भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
उद्योग की समस्या के कारण ही भारत को
चीन के साथ व्यापार घाटे का सामना करना
पड रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की भारत में अनुकूल परिस्थितियों

- (i) पर्याप्त मात्रा में श्रम बल व कुशल श्रम
- (ii) विशाल बाजार की उपलब्धता
- (iii) पूंजी व निवेश की उपलब्धता

उद्योग की समस्याएं

- (i) 'बल्लू स्केल' पर उत्पादन करने की अक्षमता
- (ii) सस्ते श्रम की अनुपलब्धता
- (iii) चीन के सस्ते उत्पादों के कारण घरेलू उद्योगों को हानि
- (iv) सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता में रमी

इसलिए हमें सस्ते मजदूरों के लिए

निम्नलिखित कदम उठाये जाने चाहिए -

- उद्योग को पर्याप्त भागा में संरक्षा व कुशल श्रम बल की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- चीनी उत्पादों पर सीमा शुल्क व हरी इंपिग शुल्क लगाकर धरेल उद्योगों का संरक्षण
- उद्योग में इकोनमी भॉफ स्कैल का प्रयोग करके विशाल भागा में उत्पादन
- शोच व नवचार को बढ़ावा
- इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति का प्रभावी विधा-व्ययन

इस प्रकार सरकार बहुआयामी प्रयासों

के माध्यम से इस उद्योग की समस्याओं का समाधान कर सकती है तथा भारत को एक अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण बना सकती है।

4. Despite registering a high growth rate in the post-reform era, India continues to witness a high incidence of poverty. Explain this paradox and suggest ways to resolve it. (150 Words) 10

आर्थिक सुधारों के बाद की अवधि में उच्च संवृद्धि दर दर्ज करने के बावजूद, भारत लगातार निर्धनता की अति व्यापकता का साक्षी रहा है। इस विरोधाभास की व्याख्या कीजिए और इसका समाधान करने के उपाय सुझाइए।

भारत 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद आज विश्व की सर्वाधिक तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है परन्तु अभी भी भारत की लगभग 22% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है-

कारण

→ ग्रुपि क्षेत्र पर अल्पाधिक जनसंख्या की निर्भरता तथा ग्रुपि क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के कारण निम्न उत्पादकता के कारण किसानों का गरीब होना

→ उच्च संवृद्धि का बेरोजगारी की दर को कम कम करने पर कोई प्रभाव नहीं रहा क्योंकि भारत में श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्र की अपेक्षा

सेवा क्षेत्र पर ज्यादा बल दिया गया है

→ भारत में संवृद्धि के लाभों को समाज के

अंतिम तबके तक पहुँचाने में सरकार असफल
रही है।

→ भारत आज बे-विश्व की 11th सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था
है परन्तु अभी भी वैश्विक ^{मुख्य} सूचकांक में
100 वां स्थान है।

समाधान के उपाय,

→ कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने पर बल

→ सामाजिक क्षेत्र में निवेश में वृद्धि
करनी

→ वित्तीय समावेशन पर बल

→ नम गहन उद्योगों पर बल देकर रोजगार
सृजन

इस प्रकार इस विरोधाभास को
समाप्त करने के लिए बहुआयामी प्रयासों
की आवश्यकता है।

5. In light of the argument that India has entered a regime of "permanent surpluses", discuss whether the time has come to remove agricultural commodities completely from Essential Commodities Act. (150 Words) 10
इस तर्क के आलोक में कि भारत "स्थायी अधिशेषों" के युग में प्रवेश कर गया है, चर्चा कीजिए कि क्या कृषि जिनमें को आवश्यक वस्तु अधिनियम से पूर्णतया हटा देने का समय आ गया है।

भारत विश्व का द्वितीय ~~खाद्य~~ खाद्य
उत्पादक ~~का~~ देश है तथा दुग्ध उत्पादन में
विश्व में प्रथम स्थान है।

भारत इन उत्पादों में आत्मनिर्भरता
को प्राप्त कर चुका है तथा कई चीजों का निर्यात
भी कर रहा है।

कृषि जिनमें को आवश्यक वस्तु अधिनियम से
पूर्णतया हटाने से पक्ष में वरि

(i) इससे इनके निर्यात में वृद्धि की
संभावना है जिससे किसानों की आय
में वृद्धि होगी

(ii) इससे इनके भण्डारण करके कृषि उपज
की अधिकता को नष्ट होने से
बचाया जा सकेगा तथा इसका प्रयोग

→ युवा रू समय सिधा जा सके॥

विपक्ष में बर्न

- भारत में कृषि जितनी रू उत्पादन में क्षेत्रीय
असमानता रू भव! इनकी रू सीमतों व में
भारी आस्चरता रहती रू
- कालाबाजारी एवं जमाखोरी में वृद्धि हो
सकती रू
- कमी रू समय महंगाई में वृद्धि हो सकती रू
- खाद्य सुरक्षा पर प्रतिफल प्रभाव की संभावना

भवन! इस संबन्ध में सभी हितधारकों
से व्यापक विचार-विमर्श करके ही किसी
निर्णय पर पहुँचा जाना चाहिए।

6. The 1988 National Forest Policy (NFP) was visionary in its scope and ambition. However, there is a need for a new forest policy in the current context. Discuss. (150 Words) 10

1988 की राष्ट्रीय वन नीति (NFP) अपने विषय-क्षेत्र और लक्ष्य की दृष्टि से दूरदर्शी थी। हालांकि, वर्तमान संदर्भ में एक नवीन वन नीति की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

भारत में दृष्टे वनों के क्षेत्रफल
को देखते हुए राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की
घोषणा की गई।
नीति के प्रावधान

- (i) वन क्षेत्र को कुल भौगोलिक क्षेत्र का न्यूनतम 33% करना
- (ii) वनों का विस्तृत सर्वेक्षण करके वन स्थिति का पता लगाना
- (iii) प्रतिपूरक वनारोपण पर बल
- (iv) सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी पर बल देना
- (v) वन क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार तथा शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना

वर्तमान में नई नीति की आवश्यकता

- 1988 की नीति के बाद के परिदृश्य व जलवायु परिस्थितियों में व्यापक बदलाव
- पूर्ववर्ती नीति का अप्रभावी रियान्वयन
- वनारोपण हेतु विनीय सुविधाओं का अभाव
- प्रतिपूरक वनारोपण की अपेक्षा

अतः नवीनतम प्रौद्योगिकी एवं उपायों का प्रयोग कर वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नई वन नीति को लाये जाने पर विचार आवश्यक है।

7. How does rapid urbanization increases the vulnerability to major disasters?
Explaining with examples, suggest measures to develop disaster-resilient cities. (150 Words) 10

द्वुत शहरीकरण प्रमुख आपदाओं के प्रति सुभेद्यता को कैसे बढाता है। उदाहरणों के साथ व्याख्या करते हुए, आपदा-प्रत्यास्थ शहरों का विकास करने के उपाय सुझाए।

शहरीकरण ने जहां एक तरफ मानव

जीवन को गुणवत्ता पूर्ण बनाया है वहीं दूसरी ओर अनेक समस्याओं एवं आपदा के प्रति सुभेद्यता भी बनाया है

आपदा सुभेद्यता में वृद्धि -

→ शहरों में इंक्रीट की संरचनाओं व पक्की सड़कों के कारण भूजल रिमाव में इमी, इभलित जब भी अचानक ~~बर्फ~~ ज्यादा पानी बरसने पर षाट की समस्या। जैसे भुंवरई की षाट।

→ अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य संबंधी आपदा। जैसे- दिल्ली में प्रदूषण की समस्या

→ आर्द्रभूमियों पर इट्टे के कारण भूजल में

इसी के कारण जलमिषाव की समस्या । जैसे
वैावुत शहर का जलमिषाव

→ इसी के साथ शहरों के इमिभोजित वसाव के
कारण भूकंप जैसी आपदा के समय भारी -
विनाश

आपदा- प्रभास्य शहरों के विकास के उपाय

(i) आपदा प्रबंधन पर सेंडर्ड फ्रेमवर्क (2015-30)
का पालन करके निभोजित शहरीकरण

(ii) आडिभूमियों का संरक्षण

(iii) भूजल रिचार्ज एवं पर्याप्त जल निष्कापी
पर बल

(iv) भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण

इसी के साथ व्यापक जनजागृकवण
का उचित नीति निर्माण के माध्यम से सुरक्षित
व आपदा प्रभास्य शहरों का निर्माण किया
जा सकता है।

8. Explain DNA profiling and highlight its forensic application. Also discuss the significance of DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018 in this regard. **(150 Words) 10**

डीएनए प्रोफाइलिंग की व्याख्या कीजिए और इसके फॉरेंसिक अनुप्रयोग पर प्रकाश डालिए। साथ ही, इस संबंध में डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2018 के महत्व पर चर्चा कीजिए।

डीएनए प्रोफाइलिंग में व्यक्ती के डीएनए के क्षारों के अनुक्रमण (Sequence) का अध्ययन कर उनको सुरक्षित करने का तथा पुनःप्राप्ति करने का कार्य किया जाता है।

डीएनए प्रोफाइलिंग के फॉरेंसिक अनुप्रयोग

- (i) भूतकों के परिजनों की पहचान करने के लिए
- (ii) लोकार के अपराधी की पहचान हेतु
- (iii) संग्रह की वैधता के दावों की जांच हेतु
- (iv) अपराध नियंत्रण में अनुप्रयोग

परन्तु इस जानकारी का गलत इस्तेमाल कर व्यक्ती की निजता का हानन किया जा सकता है। इसे रोकने के लिए ही डीएनए प्रौद्योगिकी

विनियमन बिल लाया गया है -

प्रमुख प्रावधान -

- (i) डीएनए प्रोकार्डिंग विनियामक बोर्ड की स्थापना
- (ii) प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए मानक
- (iii) डेटा की सुरक्षा के प्रावधान जैसे बिना अनुमति के डीएनए से-पल नहीं लेना

बिल का महत्व -

- (i) अपराधों को लाइन करने में तीव्रता → तीव्र-यार्थ
- (ii) संधानि दलों का शीघ्र निपटारा
- (iii) अपराधियों के इलेक्ट्रॉनिक डालवेज बनाने में सहायता

~~(iv) ...~~

परन्तु इस लेबन्ध में इसके दुर्लभयोगों

को रोकने की भी पर्याप्त कोशिश होनी चाहिए ताकि किसी की निजता का उल्लंघन न हो सके

9. What is meant by the term Blue Water Capabilities? In this context, identify the key measures that have been undertaken to enhance the blue water capabilities of the Indian Navy. (150 Words) 10

ब्लू वाटर क्षमताएँ पद का क्या अर्थ है? इस प्रसंग में भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर क्षमताओं का संवर्द्धन करने के लिए किए गए प्रमुख उपायों की पहचान कीजिए।

ब्लू वाटर क्षमता से वास्तविक क्षमता को सुरक्षा व्यापक सुरक्षा करने से है, समुद्री

भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर क्षमताओं के संवर्द्धन के उपाय

- पर्याप्त मात्रा में जहाज व उपकरण तथा हथियारों की उपलब्धता
- प्रौद्योगिकी का व्यापक इस्तेमाल
- हिन्द महासागरीय देशों के साथ प्रत्यक्ष द्विपक्षीय संपर्क पर बल
- जहाज के तीनों अंगों के मध्य समन्वय
- परमाणु प्रौद्योगिकी की पूर्वाभ्यासिकता को से नैतिक करना

→ व्यापक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास

→ विनीय व नीतिगत सहयोग की उपलब्धता

10. Identify the factors that make India vulnerable to drug trafficking? Also discuss the key steps taken to deal with it in our country. (150 Words) 10

उन कारकों की पहचान कीजिए जो भारत को ड्रग तस्करी के प्रति सुभेद्य बनाते हैं? साथ ही, हमारे देश में इससे निपटने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिए।

भारत में वर्तमान में व्यापक स्तर पर ड्रग तस्करी का विस्तार है जो राष्ट्रीय सुरक्षा व जनजीवन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं

भारत की सुभेद्यता के कारण -

- (i) भारत का दो प्रमुख ड्रग उत्पादक क्षेत्रों 'गोल्डन ट्रायंगल' तथा स्वर्ण अर्धचन्द्रमा (पाक, अफगानिस्तान व ईरान) के पास होना
- (ii) भारत - नेपाल व भारत - भूटान की खुली सीमा के कारण निगरानी का अभाव
- (iii) सीमा प्रबंधन के समझ आने के चुनौतियों - जैसे - बास की अपर्याप्तता इत्यादि
- (iv) भारत में बड़ी मात्रा में अवैध प्रवासियों का होना तथा उनका इन कार्यों में संलग्न होना

निपटने के उपाय.

- (i) खुली सीमाओं की निगरानी
- (ii) सूचीकृत सीमा प्रवन्धन पर बल देना
- (iii) अप्रवासियों (अवैध) के प्रवेश पर रोक
लगाना
- (iv) कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूर्व क्रियात्मक
कार्रवाई व व्यापक समन्वय
- (v) सीमा पर पर्याप्त वाइवडी व निगरानी उपकरण
लगाना

इसी के साथ घड़ौली देशों के साथ
इस संबंध में सहयोग पर बल देना चाहिए।

11. How do higher global crude oil prices affect the Indian economy? What steps can be taken to gradually insulate India from global oil price volatility in the long term? (250 Words) 15

कच्चे तेल की उच्च वैश्विक कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं? दीर्घावधि में भारत को वैश्विक तेल की अस्थिर कीमतों से सुरक्षित करने के लिए उत्तरोत्तर कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं?

भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग 80% निर्यात के माध्यम से पूरा करता है। इसलिए तेल की कीमत में कोई भी परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित करता है।

कच्चे तेल की उच्च वैश्विक कीमतों का अभाव-

→ कच्चे तेल की उच्च ^{कीमत} के कारण भारत में भुगतान क्षमता में तीव्र वृद्धि होती है।

→ इससे परिवहन साधनों के ईंधन के महंगा होने से वस्तुओं की परिवहन लागत बढ़ जाती है।

→ कई उद्योग जो कच्चे तेल या पेट्रोलियम को इंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, उनकी लागतों में वृद्धि हो जाती है।

→ इसी के साथ सरकार के राजकोष पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसको करों की कम मात्रा प्राप्त होती है

वैश्विक तेल की आर्थिक कीमतों के प्रति उपाय -

(1) अल्पकालिक उपाय -

- ईंधन पक्ष वाहनों का प्रयोग करना चाहिए
- घरेलू तेल की खोज और उसके उत्पादन पर बल देना चाहिए
- सार्वजनिक परिवहन की ओर ध्यान देना चाहिए
- सरकार की नई हाइड्रोकार्बन लाइसेंसिंग नीति इसमें सहायक हो सकती है

(2) दीर्घकालिक उपाय -

- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर

दृष्टान उन्मुख करना चाहिए

→ नवीकरणीय इर्जा क्षेत्र में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए

→ इलेक्ट्रिक वाहनों पर बल दिया जाना चाहिए

इसी के साथ ही सरकार को 'बोयोफ्यूल' श्रेय पर भी बल देना का प्रयास करना चाहिए ताकि तेल की सीमों में उतार-चढ़ाव की अस्थिरता से बचकर आर्थिक विकास पर बल दिया जा सके ।

12. Critically discuss the role of private sector in skill development in India in recent years. In this context, what are the measures required to improve oversight as well as financing in the skill development sector?

(250 Words) 15

हाल के वर्षों में भारत में कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका की समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में, कौशल विकास क्षेत्र में निरीक्षण और साथ ही वित्तीयन में सुधार के लिए कौन-से उपाय आवश्यक हैं?

रुक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल क्रमिकों में से केवल 5.36% क्रमिकों के पास औपचारिक कौशल प्रशिक्षण है। इसलिए भारत में इस परिदृश्य में सुधार हेतु सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र द्वारा भी अनेक प्रयास किए गए हैं जैसे-

- (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना में सरकार के साथ सहयोग कर क्षेत्रीय कौशल परिषदों के माध्यम से लोगों को कौशल प्रशिक्षण देना
- (ii) नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना

परन्तु ये सभी उपाय अत्यन्त सीमित स्तर पर किए जाये हैं वचा इनके

लिए पर्याप्त भाजा में धन एवं संस्थागत सुविधा का अभाव रहा है। साथ ही ये कुछ ही क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिस कारण कौशल परिदृश्य में क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है।

अतः इस क्षेत्र के उद्धार के लिए निजी क्षेत्रों को निवेश एवं साधनों में वृद्धि करना होगा।

कौशल विकास क्षेत्रों में निरीक्षण के उपाय -

(i) राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के माध्यम से कौशल विकास गुणवत्ता का 'राष्ट्रीय स्किल योग्यता फ्रेमवर्क (NSRF)' के अनुसार प्रमाणन एवं विनियमन

(ii) प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एक सशक्त निगरानी प्रणाली की स्थापना करना जिसमें क्षेत्र-स्तर पर समन्वय हो

विनीयन में सुधार के उपाय-

- (i) कौशल विकास संस्थानों को प्रदर्शन के अनुसार विनीय सहायता उपलब्ध करवाना
- (ii) परिणाम आधारित (Outcome based) विनीयन को प्रोत्साहन देना
- (iii) सार्वजनिक विनीयन के साथ-साथ निजी क्षेत्र द्वारा भी कौशल विकास क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना

इन्हीं उपायों के कारण भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभों का समुचित उपयोग कर विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर होगा।

13. The e-commerce sector has been booming in India for the last few years. Examine the need for its regulation in light of the recently proposed draft e-commerce policy. Further, identify the challenges that the sector is currently facing. (250 Words) 15

ई-कॉमर्स क्षेत्रक विगत कुछ वर्षों से भारत में तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में प्रस्तावित ड्राफ्ट ई-कॉमर्स नीति के आलोक में इसके विनियमन की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। साथ ही, इस क्षेत्रक द्वारा वर्तमान में सामना की जाने वाली चुनौतियां की पहचान कीजिए।

भारत का ई-कॉमर्स क्षेत्र एक तीव्र गति से वृद्धि करने वाला क्षेत्रक है जिसमें अनेक विश्वस्तरीय कंपनियाँ अपना व्यवसाय संचालित कर रही हैं।

परन्तु ई-कॉमर्स क्षेत्र के विकास में भारत में विनियामकीय ढाँचे का अभाव है जिसके कारण अनेक बाह्य ग्राहकों के हितों के उल्लंघन का भावना सामने आता है। इसी के निवारण तथा ई-कॉमर्स क्षेत्र के समुचित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा ई-कॉमर्स नीति का प्रस्ताव लाया गया है।

ई-कॉमर्स नीति के प्रावधान

- ई-कॉमर्स क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना
- एक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना
- विवादों के तीव्र निपटारे द्वारा ईज ऑफ

दुर्बल विजनेस में सहायता ।

- ग्राहकों को उचित कीमत पर सही वस्तु एवं सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- इसी के साथ ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए कुशल लोगों का कार्यबल तैयार करना

इस प्रकार नीति द्वारा भारत में ग्राहकों के हितों की सुरक्षा तथा इस क्षेत्र के पर्याप्त विकास दोनों पर ध्यान दिया गया है।

ई-कॉमर्स क्षेत्र की वर्तमान समय में चुनौतियाँ

- (i) इस क्षेत्र में व्यवसाय के विनियमन तथा निगलानी के लिए संस्थागत संरचना का अभाव
- (ii) विनियमों के अभाव के कारण ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी होने के फलस्वरूप ग्राहकों के विश्वास व शक्ति में कमी

- (iii) ई- कॉमर्स में निवेश प्रोत्साहन नीतियों का
अभाव
- (iv) ई- कॉमर्स संबन्धी कंपनियों द्वारा ग्राहकों
का डाटा संग्रहण कर उसका अनुचित
इस्तेमाल पर रोक लगाने संबन्धी नीतियों
व संरचना का अभाव

अतः सरकार को तुरंत इस नयी
नीति का डियान्वयन सुनिश्चित कर इन चुनौतियों
का निवारण करने का प्रयास करना चाहिए ताकि
वैश्विक ई- कॉमर्स क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी
को बढ़ाया जा सके।

14. Explaining the importance, highlight the achievements of dairy sector in India. Examine whether over-production is the reason for the problems being faced by the dairy industry. Give some solutions to address the problems. (250 Words) 15

भारत में डेयरी क्षेत्र के महत्व की व्याख्या करते हुए, इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। परीक्षण कीजिए कि क्या अति-उत्पादन डेयरी उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का कारण है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाइए।

भारत विश्व के सर्वाधिक पशुधन संचयन वाला देश है तथा 1960 के दशक की दुग्ध दुग्ध क्रांति के कारण भारत आज दुग्ध क्षेत्र ~~अग्रणी~~ में आत्मनिर्भर देश है।

डेयरी क्षेत्र का महत्व-

- (i) लोगों को प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाकर खाद्य सुरक्षा व पोषण सुरक्षा में योगदान
- (ii) दुग्ध के अनेक उत्पादों के कारण निर्यात आय में वृद्धि
- (iii) बढ़ते शहरीकरण हेतु भ्रूण की पूर्ति में सक्षमता
- (iv) गरीब व सीमान्त क्लिष्टानों को रोजगार

की उपलब्धता

डेयरी क्षेत्र की उपलब्धियां

- (i) भारत वर्तमान में ~~खुद~~ दुग्ध क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश है
- (ii) प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन लगभग 280 ग्राम/दिन हो चुका है
- (iii) भारत की 'GDP' में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

अग्नि उत्पादन

- भारत में शीत भण्डारण या कोल्ड चेन सेबन्धी अवसंरचनात्मक कमी के कारण दुग्ध की क्वालिटी होती है तथा अग्नि उत्पादन के कारण मूल्यों में गिरावट के कारण किसानों की हानि उठानी पड़ती है
- भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्रों का असमान वितरण होने के कारण जब अग्नि उत्पादन

होता है जो उसे निम्न उत्पादन के क्षेत्र में
पहुँचाने में विफलता के कारण दुग्ध की हानि
तथा किसानों को हानि होती है

→ भारत में दुग्ध को सुखार उसको पाउडर
में बदलने संबंधी प्रसंस्करण सुविधाओं के
अभाव के कारण दुग्ध हानि

उपाय-

- (i) कोल्ड चेन संबंधी अवसंरचना का निर्माण
- (ii) एक राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना ताकि
क्षेत्रीय दुग्ध उत्पादन असंतुलन का
समाप्त किया जा सके
- (iii) दुग्ध के प्रसंस्करण पर बल देना ताकि अति
उत्पादन के समय इसकी अधिक मात्रा
को संरक्षित रखा जा सके।

इसी के साथ दुग्ध के निर्यात को
बहाल देकर अति उत्पादन से अपनी समस्या
का निवारण कर किसानों को सुरक्षा प्रदान
की जा सकती है।

15. There has been a focus on Textile and Apparels industry in India in recent years. Elaborate the potential of this industry and the challenges that lie in achieving it. What steps have been taken in this regard? (250 Words) 15

हाल के वर्षों में भारत में वस्त्र एवं परिधान उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस उद्योग की संभावित क्षमता और उसे हासिल करने में निहित चुनौतियों की सविस्तार वर्णन कीजिए। इस संबंध में कौन-से कदम उठाए गए हैं?

सरकार द्वारा अनेक योजनाओं

जैसे वस्त्र व परिधान उद्योग हेतु शक्ति-चाबित करछा
हेतु वित्तीय सहायता इत्यादि के माध्यम से
वस्त्र व परिधान क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया
जा रहा है।

वस्त्र व परिधान क्षेत्र की संभावित क्षमता-

→ भारत में इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त कुच्चा
माल उपलब्ध है अतः कुच्चे माल का
आधान नहीं करना पड़ेगा।

→ भारत की विशाल जनसंख्या इस क्षेत्र के
लिए बाजार का काम कर सकती है तथा
निर्घात में भी सहायता मिल सकती है।

→ यह एक श्रम गहन क्षेत्र है जिससे भारत

में बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है

→ इसी के साथ कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को इसमें स्थानान्तरित कर कृषि क्षेत्र पर दबाव कम किया जा सकता है।

क्षेत्र की चुनौतियाँ

- (i) भारत में गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल (कपास) की कम उपलब्धता
- (ii) कौशल युक्त श्रमिकों का अभाव
- (iii) 'मिचेल्स फाइबर' के रूपों के साथ प्रतिस्पर्धा
- (iv) अनेक देशों जैसे चीन, बांग्लादेश, वियतनाम इत्यादि के साथ विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धी
- (v) इस क्षेत्र में संस्थागत अज्ञान के प्रवाह का निम्न स्तर

समाधान के कदम.

- (i) वसा बुनाई वालों को ~~शक्तिशाली~~ शक्तिचालित करवा प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय एवं कृषि मंत्रालय की योजना
- (ii) इस क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि के अंशदान को सरकार द्वारा वहन करना
- (iii) कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से कुशल श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना

इसी के साथ भाग सृजित करने, गुणवत्तापूर्ण उच्चाभाल की आपूर्ति तथा निर्यात संवर्धन पर भी पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

16. How do transportation corridors in biodiversity rich areas impact the wildlife? Examine the current policy framework in this regard. Also, suggest measures to minimise the negative effects while balancing the need for development. (250 Words) 15

जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में परिवहन गलियारे वन्य-जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? इस संबंध में वर्तमान नीतिगत ढांचे का परीक्षण कीजिए। साथ ही, विकास की आवश्यकता को संतुलित करते समय इसके नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम करने के उपायों का सुझाव दीजिए।

भारत अपनी भौगोलिक विविधता के कारण एक समृद्ध जैव विविधता वाल मेगाडायवर्स देश है परन्तु वर्तमान परिवहन गलियारों के विकास ने जैव विविधता के समक्ष संकट खड़ा कर दिया है जिसका तत्काल समाधान आवश्यक है।

परिवहन गलियारा विकास का वन्यजीवन पर प्रभाव

- उनके भावालों की क्षति के कारण उनके अस्तित्व पर संकट।
- सड़क या रेल मार्ग धार करते समय वाहनों से शरारत से वन्य जीवों की मृत्यु।
- वाहनों के चलने से ध्वनि प्रदूषण है

कारण वन्य-जीवों की ~~जीवन~~ जीवन शैली पर
नकारात्मक प्रभाव।

→ ~~वन्य~~ वाहनों के धुंए के कारण ~~जलवायु~~ वायु
प्रदूषण के फलस्वरूप वन्य जीवों की उत्पादकता
व प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव।

भारत में हम संबन्ध में नीतिगत ढांचा.

- (i) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972।
- (ii) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत
पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन।
- (iii) जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002।
- (iv) भारत द्वारा 'जैव विविधता अभिसमय (CBD)' पर
हस्ताक्षर इत्यादि।

कृषियाँ

- (i) नीतियों के क्रियान्वयन में नौकरशाही की
अप्रभाविता
- (ii) पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्रभाव को गंभीरता
से न लेना

→ लोगों में जागरूकता का अभाव ।

संबन्धित उपाय -

- (i) परिवहन आलियारे के विकास के समय न्यूनतम जैव-विविधता वाले स्थानों का चयन ।
- (ii) परिवहन मार्गों को दोनों ओर से बाड़ से ढक करना तथा वन्य जीवों के पारगमन के लिए पुलों का व अण्डरपास का निर्माण ।
- (iii) वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्युत चालित ट्रेन तथा CNG वाहनों का प्रयोग
- (iv) इस क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध
- (v) विस्तृत पर्यावरण प्रभाव सांकलन

इसलिए विकास एवं जैव विविधता संरक्षण के मध्य संतुलन बनाने के लिए सरकार को उपर्युक्त उपायों के साथ-साथ लोगों में जागरूकता का प्रसार होने ही की आवश्यकता है।

17. The potential of technology to aid farmers in increasing productivity as well reducing susceptibility to climate change remains underutilized. Identify the reasons for the same and suggest measures to improve technological penetration in agriculture. **(250 Words) 15**

उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता को कम करने हेतु किसानों की सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता का पूर्ण दोहन नहीं हो पाया है। इसके कारणों की पहचान कीजिए और कृषि में प्रौद्योगिकी प्रसार में सुधार हेतु उपाय सुझाइए।

वर्तमान में भारत का कृषि क्षेत्र

लगभग 52% जनसंख्या के जीवन-निर्वाह का साधन है परन्तु यह क्षेत्र ~~कम~~ निम्न उत्पादकता एवं जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से जूझ रहा है।

इस समस्या को प्रौद्योगिकी के

प्रयोग से दूर करने में सहायता मिल सकती है, परन्तु भारत में प्रौद्योगिकी की क्षमता का पूर्ण दोहन नहीं हो पाया है-

- जल संरक्षण की तकनीकों का कम प्रयोग
- बीज सुधारों पर कम बल
- सूक्ष्म सिंचाई पर कम बल
- मूला विरोधी फसलों की तकनीक पर कम ध्यान

प्रौद्योगिकी की क्षमता के निम्न दोहन के कारण .

- भारत में लगभग 65% किसान सीमान्त व लघु किसान हैं जो प्रौद्योगिकी की क्षमता का वहन नहीं कर सकते।
- सरकार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध व अनुसंधान पर कम ध्यान दे रही है।
- किसानों के पास सूक्ष्म सिंचाई जैसी तकनीक को अपनाने के लिए संस्थागत ऋण तक पर्याप्त पहुंच का अभाव है।
- इसी के साथ सरकार इस संबन्ध में किसानों के मध्य व्यापक जागरूकता प्रसार करने में असफल रही है।

इसीलिए कृषि क्षेत्र के उछार के लिए प्रौद्योगिकी प्रसार की तत्काल आवश्यकता

हैं जिसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए -

- (i) कृषि प्रौद्योगिकी के शोध व अनुसंधान हेतु पर्याप्त संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था करना
- (ii) किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, प्राथमिकता क्षेत्र उद्योगी इत्यादि उपायों के माध्यम से संस्थागत ऋण उपलब्ध करवाना
- (iii) किसान चैनल व अनेक मोबाइल एप के माध्यम से जागरूकता का प्रसार

इसी के साथ किसान उत्पादक संगठनों व चा सहकारी संस्थानों की स्थापना द्वारा किसानों की प्रौद्योगिकी प्रेरित कृषि की ओर अग्रसर किया जा सकता है।

18. What is Intelligent Transportation System (ITS)? Explaining the need of ITS in India, identify the challenges in deploying it. (250 Words) 15

कुशल परिवहन व्यवस्था (इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम: ITS) क्या है? भारत में ITS की आवश्यकता की व्याख्या करते हुए, इसके परिनियोजन में आने वाली चुनौतियों की पहचान कीजिए।

कुशल परिवहन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था

होती है जो प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर कम लागत में अधिक निर्गत प्रदान करती है। जैसे - पॉड टैक्सी, मेट्रो ट्रेन, हाइपरलूप इत्यादि।
भारत में आवश्यकता -

- (i) भारत में शहरीकरण के कारण परिवहन सुविधाओं पर दबाव के कारण फलस्वरूप जाम की समस्या।
- (ii) वाहनों से होने वाले प्रदूषण के कारण जीवन की गुणवत्ता में कमी।
- (iii) जाम के कारण शहरी गतिशीलता (mobility) में कमी जिससे लोगों को अपने गन्तव्य तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है।

(iv) आने वाले समय में 2030 तक भारत में शहरी जनसंख्या के 600 मिलियन होने का अनुमान है इसलिए एक कुशल परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता समीचीन प्रतीत होती है।

(v) भारत के प्रमुख महानगरों में परिवहन सुविधाओं की निम्न स्थिति को देखते हुए इसकी आवश्यकता।

प्रमुख कुशल परिवहन व्यवस्था-

- (i) पॉड बैंसी
- (ii) हाइपरलूप ट्रेन
- (iii) मेट्रो ट्रेन
- (iv) डीजल एवं इलेक्ट्रिक कारें
- (v) स्वचालित कारें

परिवहन योजना की चुनौतियां

→ इन परिवहन व्यवस्थाओं के लिए भारी

- भाजा में उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है जिसका भारत के पास अभाव है
- प्रौद्योगिकी आयात के कारण वित्तीय बोझ
 - भारत में इन व्यवस्थाओं के 'इंस्टोलेशन' एवं परिचालन के लिए विशेषज्ञता का अभाव
 - भारत में गरीबी जैसी समस्याओं का पहले निपटारा आवश्यक

इसलिए इन व्यवस्थाओं से लाभ लेने पूर्व व्यापक-स्तर पर शोध एवं विचार-विमर्श की आवश्यकता है तथा इसके लिए पर्याप्त भाजा में वित्तीय संसाधन भी आवश्यक होंगे।

19. Explain the concept and significance of Data Localisation. Also discuss its limitations in strengthening law enforcement efforts in the context of Srikrishna Committee report and the draft Personal Data Protection Bill, 2018. (250 Words) 15

डेटा लोकलाइजेशन की अवधारणा और महत्व की व्याख्या कीजिए। साथ ही, श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट और ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2018 के संदर्भ में कानून प्रवर्तन प्रयासों को सुदृढ़ करने में इसकी सीमाओं की चर्चा कीजिए।

वर्तमान में अनेक इंटरनेट प्रदाता तथा सोशल मीडिया कंपनियों के सर्वर विदेशों में स्थित हैं जिससे कारण डेटा चोरी का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी से बचने के लिए इन कंपनियों के सर्वर को भारत में स्थापित करके डेटा निर्यात से बचने की डिया को डेटा लोकलाइजेशन कहा जाता है।

डेटा लोकलाइजेशन के लाभ -

- (i) देश में डेटा के स्थित होने से उसके चोरी होने का खतरा कम
- (ii) विदेशी शक्तियां उस डेटा का प्रयोग देश के चुनाव या राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने में कर सकती हैं, परन्तु डेटा स्थानीयकरण से इससे निजात मिलेगी

→ डैश सर्वर को स्थानीय विनियमों के अंतर्गत लाया जा सकता है जिसे डैश तथा नागरिकों नागरिकों की निजता की सुरक्षा में वृद्धि होगी।

विभिन्न डैश चोरी की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने जस्टिस श्रीरङ्गा की अध्यक्षता में एक समिती गठित की थी जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

डैश सुरक्षा पर रिपोर्ट-

→ डैश स्थानीयकरण पर बल

→ जस्टिस पुट्टास्वामी केस के मामले की अनुशंसाओं का समावेशन

→ 'राइट टू फॉरगोटन' का प्रावधान

→ किसी सेवा के लिए जबरदस्ती डैश प्रदान करने की सहमति न मांगना

इन्हीं सभी अनुशंसाओं के आधार

पर समिति द्वारा द्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल,
2018 भी सरकार को प्रदान किया गया है

डेटा लोकेशन एजेंशन की सीमाएं

- (i) अनेक कंपनियों के साथ इनके प्रवर्तन हेतु
समझौता करना पड़ेगा। इससे कंपनियां भारत
में व्यवसाय करने हेतु हतोत्साहित हो
सकती हैं
- (ii) डेटा स्थानीयकरण के लिए एक विशाल अवसंरचना
तथा विशेषज्ञों की भारी मात्रा में आवश्यकता
होगी

इसलिए नागरिकों के निजता के

अधिकार तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल देते
हुए सरकार को समिति की रिपोर्ट लागू
करने के संदर्भ में इन चिंतनों का शीघ्र
निवारण करना चाहिए।

20. What is the link between illegal immigration and national security? In this context, critically discuss the exercise of creating a National Register of Citizens in Assam. (250 Words) 15

अवैध आप्रवासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य क्या संबंध है? इस संदर्भ में, असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने की कवायद की समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

भारत स्वतंत्रता के घञ्चान से अवैध प्रवासन की समस्या से पीड़ित रहा है जिसमें विभाजन के प्रवासी, बिस्वनी प्रवासी, बांग्लादेशी प्रवासी, तमिल प्रवासी तथा रोहिंग्या प्रवासी प्रमुख हैं।

अवैध प्रवासन व राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संबंध

- इन प्रवासियों के कारण स्थानीय समुदायों के संसाधनों पर दबाव पड़ता है जिससे ~~असुख~~ इनके बीच तनाव उत्पन्न होने के कारण कानून व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- बेरोजगारी के कारण प्रवासी भावक पदार्थों की तस्करी, हथियारों व जाली नोटों के निर्यात, भ्रान्त तस्करी इत्यादि में संलग्न हो जाते हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है।

→ कई प्रवासी कट्टरवाद व अलगाववाद के प्रसार तथा धार्मिकवाद में संलिप्त पाये जाते हैं।

इसीलिए असम में 31 जुलाई, 2018 को NRC का पहला अधिवेशन डाफ्ट तैयार किया गया है।

सकारात्मक पक्ष -

- अवैध प्रवासियों की पहचान कर उनको निर्वासित करने में सहायता
- असम के संसाधनों व रोजगार के साधनों पर दबाव कम होगा
- अनेक अवैध गतिविधियों जैसे नकली नोटों की नकली इत्यादि पर अंकुश लगाने की संभावना है
- इतने वर्षों से अशांत असम में शांति स्थापित करने में सहयोग मिलेगा

नकारात्मक पक्ष -

- इससे प्रवासी के समय अनेकों वैध नागरिकों के लिस्ट में बाहर होने के कारण उनके

अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सभी के पास ये दस्तावेज नहीं पाये जाते

→ इससे अल्पसंख्यकों के लिए ध्वजा का माहौल पैदा हो सकता है, जिससे अविास के प्रसार की संभावना है

→ साथ ही बांग्लादेश के साथ निर्वासन सेवियों के अभाव के कारण द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जो भारत के हित में नहीं होगा

→ ~~स~~

इसलिए उपर्युक्त समस्याओं का व्यापक-विचार-विमर्श के माध्यम से समाधान कर 'NRC' को लागू करने का प्रयास करना चाहिए ताकि असम ~~क~~ में शान्ति व स्थिरता की स्थापना हो सके।